

ग्रा.वि.- 14(पू0)अर0-02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

निबंधित

श्री विजय रंजन,
उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।
(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुर्साकांटा, अररिया)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अररिया से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप कुर्साकांटा प्रखंड (जिला-अररिया) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के जापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

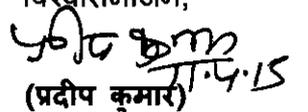
4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
7809.22277	₹ 10698635.199999999

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 7809.22277 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(प्रदीप कुमार)
सचिव

under NREGA and SGRY NFFWP. In this regard, some guidelines are given below that 100 days of employment which is permissible under the Act.

3. The incomplete works under the SGRY NFFWP, if any, will be allowed to be completed upto 30.6.2006 out of the balance funds available with the Districts.

4. Under the NREGA, only cash will be given. As such no foodgrains will be provided. The foodgrains contribution should terminate with the close of this financial year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRY and the NFFWP will not be allowed next year.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenge of the quantum of wage paid.

[This section contains several paragraphs of text that are almost entirely illegible due to heavy blacking out and poor scan quality. Only the final sentence is legible:]
Government may also be intimated to this Ministry.

Yours faithfully,

शिवराम शर्मा,
राज्यीय विकास विभाग

(आधील विभाग)
Joint Secretary

संयोजक, राजकीय विकास विभाग, दिल्ली-
0110016

3/1/06

प्रतिनिधि, नवी उप विकास आयुक्तों को सूचना के माध्यम से
सूचनायें एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten signature]
सरकार उप विभाग।

New Delhi
Dated 27 December, 2005

The Secretary,
Rural Development Department,
Government of Bihar,
Patna

SUBJECT : *Transition From the SGRY and the NFFWP towards
the implementation of NREGA in Districts identified.*

5/11/06
Sir/Madam.

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) will be implemented in select identified Districts in the initial stage (list enclosed). The National Food for Work Programme (NFFWP) and the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) will merge in these identified Districts with the Employment Guarantee Scheme, once NREGA comes into force. In this regard, following decisions on key issues have been taken by the Government of India in order to facilitate smooth transition from the NFFWP and the SGRY towards NREGA in the identified Districts that require your immediate attention.

11/11/06
1. If the NREGA is notified in an area in the current financial year, the process of demand registration will start according to the Act and the Guidelines made. The demand for employment would be met from the ongoing SGRY and the NFFWP works. The funds used will be from SGRY/NFFWP accounts. But the work allotted to those who have demanded work under the EGS will be recorded as work given for purposes under NREGA. Section 3 of the Act allows this by stipulating that until the State Government notifies its EGS, the Annual Action Plan or Perspective Plan of SGRY or NFFWP which ever is in force will be deemed to be the action plan for the scheme for the purposes of the Act. For non-NFFWP district identified under NREGA, additional funds for taking up works on NFFWP pattern are being released separately. Rs.25.00 lakh for every identified 200 districts is being released for printing of Job Cards and registers prescribed.

18/11/06
2. Under the SGRY/NFFWP, works are not opened on demand for employment but according to a plan of infrastructure needs. Once the SGRY/NFFWP works also become instruments for NREGA, they will also absorb labour that is allotted employment on them through NREGA (after registration and Job Card and Demand process is followed). Therefore, during the transition period, SGRY/NFFWP will be employing labour both

Contd...2/-

राज्य सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
द. ब. मंत्रालय, प्रकीर्ण
राज्यीय कार्यालय

जिला का नाम:- अररिया

क्रम सं०	उप विकास आयुक्त का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित साध्यान्त	वसूलीय राशि	वसूली गई राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री बाल्मीकि प्रसाद						
2	श्री कृष्णा चौधरी				12953317.12	1575725.9	127957445.3
3	श्री जी०डी० दास						
पंचायत समिति/ प्रखंड का नाम:-							
क्रम सं०	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित साध्यान्त	वसूलीय राशि	वसूली गई राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री शिव शंकर मिश्रा (1973/2011)						
1	श्री जकर रफीक (1973/1999)	6290.41	4666	1624.41	2225441.7	324900	1900541.7
2	श्री नरुण आलम (1973/1999)				2484.86	3404258.2	0
2	श्री रमनलाला (1306/1999)						3404258.2
2	मो० परवजउल्लाह (2262/1999)						
3	श्री अरुण कुमार	41747.82	10581.53	31166.29	42697817.3	111971	42585846.3
4	श्री सजय कुमार						
4	श्री शमीम अख्तर (1905/1999)						
	श्री शीशेन्द्र कुमार चौधरी	11067.29	9903.81	1163.48	1593967.6	108058	1485909.6
	श्री शिवनंदन प्रसाद						
	श्री रमेश झा						
5	श्री विजय रजन	15553.52	7704.56	7848.96	10753075.2	54440	10698635.2
6	नरपतंज	21564.56	6989.42	14575.14	19967941.8	238553	19729388.8
7	पलानी	7084.32	5760.39	1323.93	1813784.1	167277	1646507.1
	श्री सुरेन्द्र राय (1218/1999)						
	श्री शिवनंदन प्रसाद सिंह						
8	रानीवांज	52544.4	20469.36	32075.13	43942928.1	154493.9	43788434.2
	श्री शिवशंकर मिश्रा						
	श्री सुरेन्द्र राय (2218/1999)						
9	सिकरी	6068.72	3781.16	2287.56	3133957.2	416033	2717924.2
	श्री राधा मोहन राम						
	श्री अतिल कुमार (2352/1999)						
	Grand Total	161921.04	69856.23	94549.76	129533171.2	1575725.9	127957445.3